

दैनिक ज्यन्त- विचार

सम्पादकीय

मिलावटखोरी पर वृहद अभियान
देवभूमि उत्तराखण्ड में मिलावट खोरी को रोकने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जगह—जगह कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त गली मोहल्ले में बिकने वाले पेय पदार्थ तथा टेलीकॉम से भी सरकार के इस अभियान का हिस्सा रहेंगे। पिछले कुछ समय से मिलावट खोरी के कई मामले प्रदेश में सामने आए हैं जिनमें अधिकांश मामले खास तौर पर विभिन्न त्योहारों के समय देखने को मिलते हैं। इनमें नकली पनीर, मावा, कुदू का आटा, दूध आदि खाद्य सामग्रियां शामिल हैं। कुछ मौके पर दूसरे राज्यों से उत्तराखण्ड में भेजे जाने वाले नकली मावा व पनीर की बड़ी खेप पकड़ी गई है लेकिन यह आज तक पता नहीं चल पाया कि यह मिलावटी पदार्थ किन स्थानों से भेजे गए और इनका उत्पादक स्थल क्या है? यहां तक की जो सैंपल विभाग द्वारा लिए गए उनकी रिपोर्ट कभी भी ना तो सोशल मीडिया के माध्यम से और ना ही दूसरे अन्य माध्यमों से जनता तक सार्वजनिक की गई। यानी कि सैंपल लेने के बाद कार्रवाई किस स्तर पर पहुंची या हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई महज एक औपचारिकता एवं दिखावा ही साबित हो रही है क्योंकि जब तक मिलावटखोरों के पहले पायदान पर विभाग नहीं पहुंचेगा तब तक मिलावट खोरी का यह काला कारोबार थमने वाला नहीं है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अभियान तो छेड़ा है लेकिन सबसे बड़ी दिक्षत ऐसे लोगों तक पहुंचने की है जो नकली सामान बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। महज वस्तुओं की सैंपलिंग और उन्हें जब्त करने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि समान जब तो भले ही जब्त कर लिया जाए लेकिन पूरा बाजार मिलावटखोरों के जाल में फँसा हुआ है। हालांकि इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है जो बेहद जरूरी है। इसके तहत न

केवल विक्री को बल्कि खरीदारों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वह सभी खाद्य पदार्थों की अच्छी तरह से जांच परख कर ही उनकी खरीदारी करें। विभाग के साथ—साथ उपभोक्ताओं का भी एक कर्तव्य है कि वह जिस वस्तु के लिए पैसा दे रहे हैं उसकी कसौटियों को अवश्य पर परखें। सड़कों और विभिन्न ढाबों रेस्टोरेंट में बिकने वाले सामान में भी विभाग को नजर रखनी होगी क्योंकि जो कुछ भी उपभोक्ताओं को स्वाद के नाम पर परोसा जा रहा है वह कहीं से भी स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं है। फास्ट फूड के नाम पर दूषित और कोमिकल परोसे जा रहे हैं और सबसे पहला कदम ऐसे लोगों पर लगाम कसना होगा। बहरहाल सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है जो आपसे समन्वयी के साथ ही अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा मिलावटखोरों के सरगनाओं को बेनकाब करना भी बेहद जरूरी है।

एसआइआर का एक पराक्षा अभा आर होनी है। बहरहाल, अब बिहार के आर सुप्राम काट का आदेश के दम पर व आधार के जरिए मतदाता बन गए। अगर और नारंगी की चमकती परतों में वे खेलपूर्ण—मनोरंजक लग रहे थे तो डावने भी—जैसे सड़क किनारे कोई पौराणिक मेला सज गया हो। पर मेरी नजर ठहर गई मूँछों पर। गहरी, लंबी मूँछें—कहीं एके-47 के चारों ओर लिपटी हुईं, कहीं उन पर लिखा आँपेरेशन सिंदूर कामयाब। सो दशहरा भी राष्ट्रवाद की नई परत ओढ़ चुका है। सिफ़र्पौराणिक असुर रावण गी नहीं जलता, बल्कि नए दुश्मन और ताजा भिंडंत के बतौर प्रतीक भी अब जलता है। इन पुतलों को बनाने वालों को सरकार ने नहीं आदेश दिया था कि वे ये नारे लिखें। पर जब मैंने एक कारीगर से पूछा तो उसने कंधे उचकाते हुए कहा: ऐसा क्या करता है? यहाँ मैं ताजी

व्यवहार किया? उस सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया था संदिग्ध बता है। और वह ग़लत नहीं था। युद्ध के इस मौसम के बाद देश का मूड सचमुच इसी ऑफेरेशन में डूबा है। इसे हमने तब और साफ देखा जब सरकार ने एशिया कप में भारतझापकिस्तान मैच को हरी झंडी दी, लेकिन सड़क का मूड इसके उलट था—बहिष्कार की ओर। नारा वही गूँजता रहा: खून और पानी साथ नहीं बह सकते। अब यह लोहारों में भी उत्तर आया है। जब राष्ट्रीय मूड इतना अवेशपूर्ण हो, तो क्यों न रावण को भी उसके साथ रंग दिया जाए? पुतला जलाना अब अच्छाई पर बुराई की जीत नहीं, बल्कि सामूहिक गुस्से को बाहर निकालने का एक लाइसेंस प्राप्त अवसर है।

प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई को कहा अलविदा



भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई को अलविदा कह दिया है। वह दो दिनों तक मुंबई में रहने के बाद अमेरिका लौट गई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंबई में बिताए अच्छे पलों को याद किया है। फैंस को दुर्गा पंडाल में प्रियंका चोपड़ा का लुक काफी पसंद आया। प्रियंका चोपड़ा बनारसी पैटर्न के साथ पर्पल कलर के सूट में दिखी। एक्ट्रेस ने माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगा रखा था। एक्ट्रेस का देसी लुक फैंस के दिल को भा गया। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक मुंबई टूर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में एक्ट्रेस हॉलीवुड एक्शन-कॉमेडी हेड्स्टेर्ट में देखा गया था। फिल्म अप्रैल में रिलीज है। एक्ट्रेस एक साथ फिल्मों की शूटिंग कर रही है।

दा चांदनी बार सीच्छ कास्टिंग ,
तुमि, शरवरी और अनन्या
मानी जा रही हैं टॉप कंटेंडर्स

फिल्ममेकर मधुर भड़करकर की चांदनी बार, जो 2001 में रिलीज हुई थी, ने हाल ही में अपनी 24वीं वर्षगांठ मनाई। इस मोके पर इसके सीच्छ का ऐलन किया गया है। समाज की कटु सचाईयों और मुंबई की डांस बार की जिंदगी को बिना किसी लाग—लेपेट के दिखाने वाली इस व्हालासिक फिल्म ने तब्बु को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया था और भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया था। अब चांदनी बार री—ओपन्स, जिसे संदीप सिंह प्रॉड्यूसर्स करेंगे और अजय बहल डायरेक्ट करेंगे, एक बार फिर उसी संवेदनशीलता के साथ शहर की कढ़वी हकीकत को सामने लाने का वादा कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्चा इस समय फिल्म की लीड कास्टिंग को लेकर है। यह किरदार, जिसे तब्बु ने आइकॉनिक मुमताज के रूप में निभाया था, अब किसे मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि तीन युवा और टैटेंटेड अभिनेत्रीयाँ रेस में हैं, जिसमें शरवरी वाघ, अनन्या पांडे और तुमि डिमरी शामिल हैं। इंडस्ट्री में बहस छिड़ी हुई है कि इस इमोशन—द्रिंगन रोल के लिए सही चेहरा कौन होगा। क्या यह गहन किरदार निभाने की क्षमत रखने वाली शरवरी वाघ को मिलेगा?

भारत के लिए

1 दिसंबर से लंका प्रीमियर लीग की शुरुआत, भारतीय

खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
नई दिल्ली, लंका प्रैमियर लीग (एलपीएल) का छठा संस्करण 1 से 23 दिसंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसे में फैस इस टी20 लीग से जबरदस्त रोमांच की उम्मीद कर रहे हैं। पहली बार लंका प्रैमियर लीग में भारतीय ट्रिक्केटर हिस्सा लेंगे, जिनके नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों के जुड़ने से इस लीग की लोकप्रियता में इजाफा होगा। लंका प्रैमियर लीग के इस संस्करण में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। इस दौरान 20 लीग मैच और 4 नॉकआउट मुकाबले होंगे।

यह सभी मुकाबले कालबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय ट्रिक्केट स्टेडियम, कैंटी के पल्लकेले अंतर्राष्ट्रीय ट्रिक्केट स्टेडियम और दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय ट्रिक्केट स्टेडियम में खेले जाने हैं। इस टूर्नामेंट में पांच फॉयाइज़ी

खिलाड़ी लेंगे हिस्सा का यह हृतकृत पड़ा महणा, आइसासा न दा कड़ा सजा

कालबा, आईसीसी महाला विश्व कप 2025 में पाकिस्तानी ट्रिकेट टीम का राशाजनक प्रदर्शन जारी है। भारत के बलाफ रविवार को मिली करारी शिकस्त बाद अब टीम की स्टार बल्लेबाज पद्मरा अमीन पर आईसीसी ने आचार हिंता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की। सिदरा को मैच के दौरान गुस्से में अपना बल्ला मैदान पर पटकने के लिए यह जा सुनाई गई है।

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम रविवार, 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का अहम काबला खेला गया था। भारतीय टीम ने दोनों बल्लेबाजों को दो पारियां दिए गयीं।

248 रनों का लद्दी दिया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम बिखर गई और केवल 159 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र अनुभवी बल्लेबाज सिदरा अमीन ने ही संघर्ष किया और 81 रनों की शानदार पारी खेली।

मैच के 40वें ओवर में जब सिदरा भारतीय स्पिनर स्लेह राणा की गेंद पर आउट हुई, तो वह अपनी हताशा पर काबू नहीं रख सकी। टीम की हार और अपने शतक से चूकने की निराशा में उन्होंने पवेलियन लौटे समय गुस्से में अपना बल्ला जोर से मैदान पर पटक दिया। उनकी यह हक्कत मैदान पर लगे कैमरों में कैद हो गई।

अतराइट्रोप ट्रिकेट पारिषद (टीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सिदरा अमीन ने आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया है, जो ट्रिकेट उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित है। मैच रेफरी ने सिदरा की इस हक्कत को लेवल-1 का अपराध माना।

सजा के तौर पर सिदरा को आधिकारिक फटकार लगाई गई है और उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिया गया है। हालांकि, लेवल-1 का अपराध होने के कारण उनकी मैच फीस नहीं कटी गई है। यह हार और सजा पाकिस्तानी टीम के लिए एक दोहरे झटके रही रहा है।

एसआईआर के कई सवाल अब भी अनसुलझे



अजीत द्विवेदी

A photograph showing a group of people, including several children, gathered outdoors. In the background, there is a building with a prominent red and white domed structure, likely a government or educational institution. Some individuals in the foreground are holding what appear to be documents or papers, possibly related to the 'Swachhta Abhiyan' mentioned in the text.

के विशेष अंतर की आयोग ने उत्तर दी है, 42 लाख अंतर शुरू करतदाताओं व थी, जो अख हो गई कि सिर्फ असल में यह सात दिख रही से हैं, जो आयोग ने

A close-up photograph focusing on a person's hands. The hands are positioned as if holding a small, rectangular object, possibly a piece of evidence or a document. The background is blurred, suggesting an outdoor setting with other people visible.

एसआईआर के आंकड़े को देखने और काम पूरा करने में एक उपक्रम में कुछ लाल है कि उसके निहितार्थों को समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने जुलाई के अंत में जो मसौदा सूची जारी की थी उसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख 64 हजार नाम काट दिए गए थे। उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ लेकिन आयोग अपनी बात पर अड़ा रहा। आयोग ने कहा कि इसमें 22 लाख से कुछ ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनका निधन हो गया है, 36 लाख से कुछ ज्यादा लोग स्थायी रूप से शिफ्ट कर गए हैं और साढ़े

गई? इस सवाल का जवाब भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जिन राज्यों में एसआईआर होगा वहां ज्यादातर लोग आधार ही पेश करेंगे। इसके अलावा एक सवाल यह है कि मसौदा सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग के सामने जो दावे और आपत्तियां आई थीं उनमें से कितने को और कैसे निपटाया गया? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर का मुकदमा लड़ने वाले लोग बता रहे हैं कि आयोग के सामने जो आपत्तियां आई थीं उनमें 57 फीसदी ऐसी थीं, जिसमें लोगों ने अपना नाम काटने को कहा था। सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन लोगों ने मतगणना प्रपत्र भरा और मसौदा सूची में नाम आने के बाद खुद ही नाम कटवाने पहुंच गए? इसी तरह दावा किया जा रहा है कि सात सौ लोगों ने अपने को विदेशी बता कर नाम काटने को कहा। यह कैसे हो सकता है? उनका फॉर्म कैसे स्वीकार हुआ और किन दस्तावेजों के आधार पर हुआ? सबसे मजेदार दावा यह है कि 28 लोगों ने दस्तखत करके आपत्ति दर्ज कराई कि वे मर चुके हैं। क्या ऐसा होना संभव है? एसआईआर की प्रक्रिया पूरी

कर रह है। अभी अमेरिका से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क का मामला सुलझा भी नहीं है कि ट्रंप ने एच1बी वीजा का बम गिरा दिया है। एच1बी वीजा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया है। इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों, जिनमें बड़ी संख्या में आईटी से जुड़े हैं, पर गंभीर असर पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में आई पिरावट ने असर की ज़़ांकी दिखा दी है। अमेरिका का दावा है कि एच1बी वीजा का बहुत दुरुपयोग होता है।

इसकी शुरुआत उन उच्च कुशल कामगारों को अमेरिका में आने की अनुमति देने के लिए की गई थी, जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां अमेरिकी काम नहीं करते। 100,000 डॉलर के शुल्क के बाद सुनिश्चित होगा कि वास्तव में कुशल लोग ही अमेरिका आएं और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं लें। ट्रंप का तर्क है कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 281,000 लोगों को अमेरिका में प्रवेश मिलता है, तथा ये लोग औसतन प्रति वर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों का भारी लाभ उठाते हैं। हम इसे बंद करने जा रहे हैं। इस कदम का उन भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ेगा जिन्हें प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां और अन्य कंपनियां एच1बी वीजा पर नियुक्त करती हैं। ये वीजा तीन साल के लिए वैध होते हैं, जिन्हें तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आदेश के कुछ घंटों बाद शनिवार को अमेरिका में एच1बी वीजा पर रह रहे भारतीयों में भ्रम व चिंता व्याप गई। कई भारतीयों ने भारत यात्रा की अपनी योजना रद्द कर दी। जो भारत आए हुए थे उनमें जल्द से जल्द लौटने की मारामारी मच गई। हालांकि बाद में कहा गया कि यह शुल्क नये आवेदकों पर ही लागू होगा। पुराने वीजा धारक प्रभावित नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी अमेरिका के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष खरेंगे ने तल्ख टिप्पणी की कि आपके जन्मदिन पर फोन कॉल के बाद आपको जो जवाबी तोहफा मिला है, उससे भारतीय नागरिकों को दुख हुआ है। गले मिलना, खोखले नारे लगवाना और संगीत कार्यक्रम करवाना कोई विदेश नीति नहीं है। हमें अपने हितों के लिए गंभीर होना होगा।

दूसरे स्तरों तको दो!

सत्यापन आधार को अधिकारी ने ज्यादा जगहें पर थे। यह हिसाब था 65 लाख 64 हजार लोगों के नाम कटने का। अब नाम कटने का अंकड़ा 69 लाख का है। सवाल है कि साढ़े तीन लाख के करीब जो नए नाम करे हैं, वह किन लोगों के हैं? चुनाव आयोग ने इनको नाट रिकॉर्ड की श्रेणी में रखा था और नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने खुद ही बताया है कि बिना पक्ष सुन किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। सो, जाहिर है कि इन साढ़े तीन लाख लोगों का पक्ष सुन कर इनका नाम काटा गया होगा। तो अब सवाल है कि इनके दस्तावेजों में क्या गड़बड़ी थी? क्या इनके पास आधार भी नहीं था? या आधार था लेकिन आयोग को उसकी प्रामाणिकता पर संदेह था?

ध्यान रहे अनेक लोगों की कहानियां आ रही हैं कि उनके पास सिर्फ आधार था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दम पर वे आधार के जरिए मतदाता बन गए। अगर विहार के

र किसी और दस्तावेज को मांग की ज़रूरत क्योंकि आगे जिन राज्यों में प्रवासी आर होगा वहाँ ज्यादतर लोग आधार ही पेश करेंगे। इसके अलावा एक बाल यह है कि मसौदा सूची जारी होने वाल चुनाव आयोग के सामने जो दावे पर आपत्तियां आई थीं उनमें से कितने वाले और कैसे निपटाया गया? यह सवाल अलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक प्रवासी आर का मुकदमा लड़ने वाले यह बता रहे हैं कि आयोग के सामने जो आपत्तियां आई थीं उनमें 57 फीसदी भी थीं, जिसमें लोगों ने अपना नाम बदलने को कहा था। सवाल है कि ऐसा से हो सकता है कि जिन लोगों ने नाम बदलना प्रपत्र भरा और मसौदा सूची में उन्हें अपने के बाद खुद ही नाम कटवाने चाहिए? इसी तरह दावा किया जा रहा कि सात सौ लोगों ने अपने को विदेशी नाम करना कर नाम काटने को कहा। यह कैसे सकता है? उनका फॉर्म कैसे स्वीकार आ और किन दस्तावेजों के आधार पर आ? सबसे मजेदार दावा यह है कि 28 लोगों ने दस्तखत करके आपत्ति दर्ज किया कि वे मर चुके हैं। क्या ऐसा होना भवित्व है? ऐसा आर की प्रक्रिया पूरी

के रोजगार बढ़ाने की ले रहे हैं, लेकिन हमला भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं पर कर रहे हैं। अभी अमेरिका से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क का मामला सुलझा भी नहीं है कि ट्रंप ने एच1बी वीजा का बम गिरा दिया है। एच1बी वीजा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया है। इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों, जिनमें बड़ी संख्या में आईटी से जुड़े हैं, पर गंभीर असर पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट ने असर की झांकी दिखा दी है। अमेरिका का दावा है कि एच1बी वीजा का बहुत दुरुपयोग होता है।

इसकी शुरुआत उन उच्च कुशल कामगारों की अमेरिका में आने की अनुमति देने के लिए की गई थी, जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं, जहाँ अमेरिकी काम नहीं करते। 100,000 डॉलर के शुल्क के बाद सुनिश्चित होगा कि वास्तव में कुशल लोग ही अमेरिका आएं और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं लें। ट्रंप का तर्क है कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 281,000 लोगों को अमेरिका में प्रवेश मिलता है, तथा ये लोग औसतन प्रति वर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों का भारी लाभ उठाते हैं। हम इसे बंद करने जा रहे हैं। इस कदम का उन भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ेगा जिन्हें प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां और अन्य कंपनियां एच1बी वीजा पर नियुक्त करती हैं। ये वीजा तीन साल के लिए वैध होते हैं, जिन्हें तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आदेश के कुछ घटों बाद शनिवार को अमेरिका में एच1बी वीजा पर रह रहे भारतीयों में भ्रम व चिंता व्याप गई। कई भारतीयों ने भारत यात्रा की अपनी योजना रद्द कर दी। जो भारत आए हुए थे उनमें जल्द से जल्द लौटने की मारामारी मच गई। हालांकि बाद में कहा गया कि यह शुल्क नये आवेदकों पर ही लागू होगा। पुराने वीजा धारक प्रभावित नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी अमेरिका के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष खर्रों ने तल्ख टिप्पणी की कि आपके जनन्मदिन पर फोन कॉल के बाद आपको जो जवाबी तोहफा मिला है, उससे भारतीय नागरिकों को दुख हुआ है। गले मिलना, खोखले नारे लगवाना और संगीत कार्यक्रम करवाना कई विदेश नीति नहीं है। हमें अपने हितों के लिए गंभीर होना होगा।

के बाद चुनाव आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची में 21.53 लाख लोगों के नाम जोड़े जाने की बात ही गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें 7.24 करोड़ की मसौदा सूची में से 66 लाख नाम और काटे, जबकि 1.53 लाख नाम जोड़े तो अब कुल रख्या 7.42 करोड़ हो गई। सवाल है कि ब खुद चुनाव आयोग ने एक सिंतंबर का दावे व आपत्तियां लेने की तारीख पापत होने के बाद कहा कि उसे 16.93 लाख नए नाम जोड़ने का आवेदन मिला तो यह संख्या बढ़ कर 21.53 लाख से हो गई? यह साढ़े चार लाख से बढ़ा नाम कहां से आए, जबकि आयोग कहा कि एक सिंतंबर के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा? पक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर उठाई जा रही आशंकाओं को दूर करने के लिए इन सवालों के जवाब देना चाही है।

अब रावण नहीं सच जलता है!

पर आज वे प्रतीक जानबूझकर श्रद्धावाद की पटकथा में लिखे जा रहे हैं। यह चींता है। यह दुर्घटना नहीं, यह चीं-समझी समाहिति है। और इसमें यह है, खतरा है। क्योंकि जब राजनीति श्रद्धावाद में घुलती है, तब भी लगाम राज्य हाथ में रहती है। लेकिन जब राष्ट्रवाद में घुल जाता है, तो वह अनियंत्रित जाता है। इतिहास गवाह है—भाषा, श्रद्धावाद और धर्म—ये तीन हमेशा किसी माज को आकार देने और उकसाने की बसे मजबूत शक्तियाँ रही हैं। क्योंकि वे पर्फ़नियंत्रण से नहीं, बल्कि हम कौन हैं और हमें मिलकर क्या होना है—इस हानी को गढ़ती हैं। धर्म अपने श्रेष्ठ रूप आशा और एकजुटता ला सकता है। लेकिन जैसे ही उसे राष्ट्रवाद की सेवा में झोंक दिया जाता है तो वह भविष्य की ओर संकेत करना छोड़ देता है और समाज को स्थायी वर्तमान में जकड़ देता है—हमेशा सशंकित, आक्रमक, युद्धोन्मुख। हमने यह पैटर्न देखा है—नाजी जर्मनी में, जहाँ राष्ट्रवाद नस्ली धर्म बन गया और चर्च सत्ता के औजार। इनमें, जहाँ इस्लामी गणराज्य ने धर्म को राजनीति की अकेली भाषा बना दिया। श्रीलंका में, जहाँ सिंहला—बौद्ध राष्ट्रवाद ने दशकों का रक्तपात कराया। और हमारे पड़ोस पाकिस्तान में, जहाँ राज्य पर सवाल उठाना इस्लाम पर सवाल उठाना है—और नीतीजा असहिष्णुता तथा स्थायी दुश्मनी। तो क्या हम भी अब उसी राह पर बढ़ रहे हैं? भारत अब अपने पड़ोसी जैसा होता जा रहा है। राम मंदिर का भूमिपूजन राष्ट्रवाद से इस तरह जोड़ा गया कि जिन छतों पर भगवा झंडा नहीं लहराया, वे राष्ट्रविरोधी कहलाए। कोविड के दौरान, दीया न जलाना आस्था का मामला नहीं रहा, बल्कि देशद्रोह बन गया। अब यह पटकथा और गाढ़ी हो गई है। नवात्रि सिफ़र्वत और पूजन से नहीं आती, बल्कि आदेशों से—कसाईखानों को नौ दिन बंद रखने के आदेश जैसे। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर दैवीय न्याय के औजार बन जाते हैं—मुस्लिम घर ढहाए जाते हैं, और बदुसंख्यक भीड़ इसे धर्म और राष्ट्रवाद के एक ही रंगमंच में देखती है।

भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा



निक्स कैरी शुरुआती मैच नहीं खेल किएगे। वहीं, कलाई में फैक्ट्र के चलते नेन मैक्सवेल इस टीम से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप 2027 में दो मद्देनजर रखते हुए मैथ्यू रेनशॉ और चेल ओवेन को टीम में शामिल किया ताकि ये बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकें। चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली के मुताबिक, टी20 टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक साथ रखा गया है, लेकिन कुछ खिलाड़ी एशेज सीरीज और शेफील्ड शील्ड खेलेंगे, जिसके तहत कैमरून ग्रीन को टी20 टीम में शामिल

भारत से हार का डबल झटका, पाकिस्तानी बल्लेबाज को ये हरकत पड़ी महंगी, आईसीसी ने दी कड़ी सजा

कोलंबो ,आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में पाकिस्तानी ट्रिकेट टीम का राशाजनक प्रदर्शन जारी है। भारत के बलाफ रविवार को मिली करारी शिक्षण 248 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम बिखर गई और केवल 159 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र अनुभवी बल्लेबाज सिद्धा अंतर्राष्ट्रीय ट्रिकेट परिषद (ट्रृष्ट) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सिद्धा अमीन ने आईसीसी आचार सहित के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया है, जो

बाद अब टीम की स्टर्टर बल्लेबाज पदरा अमीन पर आईसीसी ने आचार हिता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की। सिद्धा को मैच के दौरान गुस्से में अपना बल्ला मैदान पर पटकने के लिए यह जा सुनाई गई है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम रविवार, 5 अक्टूबर को भारत और किस्तान के बीच विश्व कप का अहम काबिला खेला गया था। भारतीय टीम ने दूसे चौथानी तरफे द्वारा परापूर्व दूसे

अमीन ने ही संघर्ष किया और 81 रनों की शानदार पारी खेली। मैच के 40वें ओवर में जब सिद्धा भारतीय स्पिनर स्लेह राणा की गेंद पर आउट हुई, तो वह अपनी हताशा पर काबू नहीं रख सकी। टीम की हार और अपने शतक से चूकने की निराशा में उन्होंने पवेलियन लौटे समय गुस्से में अपना बल्ला जोर से मैदान पर पटक दिया। उनकी यह हक्कत मैदान पर लगे कैमरों में कैद हो गई। इसके बाद सिद्धा ने

ट्रिकेट उपकरणों के दुरुप्योग से संबंधित है। मैच रेफरी ने सिद्धा की इस हक्कत को लेवल-1 का अपराध माना। सजा के तौर पर सिद्धा को आधिकारिक फटकार लगाई गई है और उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिया गया है। हालांकि, लेवल-1 का अपराध होने के कारण उनकी मैच फीस नहीं काटी गई है। यह हार और सजा पाकिस्तानी टीम के लिए एक दोहरे झटके नहीं बनाए रखा है।

